

फेम इंडिया का दूसरा चरण

हाल ही में भारी उद्योग राज्य मंत्रालय ने लोकसभा में एक लखिति जवाब में **भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों को तेज़ी से अपनाने एवं वनिरिमाण (फेम इंडिया) योजना चरण/फेज-II** के विकास पर प्रकाश डाला।

- देश में **इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicles- EVs)** को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फेम इंडिया योजना ने इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करने और इलेक्ट्रिक गतिशीलता बुनियादी ढाँचे के वसितार में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

फेम इंडिया फेज-II:

पृष्ठभूमि:

- 'फेम इंडिया' नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन (NEMM) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 'फेम' का मुख्य ज़ोर सब्सिडी प्रदान करके इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करना है।
- योजना के दो चरण:
 - चरण-I:** यह वर्ष 2015 में शुरू हुआ और 31 मार्च, 2019 को पूरा हो गया।
- इस योजना में **हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक** तकनीक जैसे- **माइल्ड हाइब्रिड, स्टरांग हाइब्रिड, प्लग इन हाइब्रिड और बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन** शामिल हैं।

चरण-II:

- अवधि:** 1 अप्रैल, 2019 से पाँच वर्ष।
 - बजटीय सहायता:** 10,000 करोड़ रुपए।
 - लक्ष्य:** 7,090 e-बस, 5 लाख e-3 वहीलर, 55,000 e-4 वहीलर पैसेंजर कार और 10 लाख e-2 वहीलर को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करना।
 - फोकस:** सार्वजनिक और साझा परिवहन का वदियुतीकरण।
- इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिये उठाए गए कदम:**
 - EV चार्जिंग नेटवर्क का वसितार:**
 - चरण-I के तहत:** 520 चार्जिंग स्टेशन/बुनियादी ढाँचे को मंजूरी।
 - चरण-II:** 25 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 68 शहरों में 2,877 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों तथा 9 एक्सप्रेस-वे और 16 राजमार्गों पर 1,576 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी।
 - OMC के लिये पूंजीगत सब्सिडी:** 7,432 इलेक्ट्रिक वाहनों के सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिये 800 करोड़ रुपए स्वीकृत।

फेम इंडिया योजना चरण-II के तहत बेचे गए इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) का वविरण 21.07.2023 तक इस प्रकार है:

क्रमसं.	वहीलर टाइप	पंजीकृत एवं पुनर्वैध मॉडल	पंजीकृत OEM	21.07.2023 तक FAME-II के तहत बेचे गए वाहनों की कुल संख्या
1	2 वहीलर	45	25	7,40,722
2	3 वहीलर	96	28	83,420
3	4 वहीलर	34	3	8,982
कुल		175	56	8,32,824

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिये सरकारी प्रोत्साहन और सब्सिडी:

- फेम इंडिया योजना चरण-II:**
 - करेताओं के लिये EV की खरीद कीमत में अग्रिम कटौती।
- ऑटोमोटिव क्षेत्र के लिये उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन (Production Linked Incentive Scheme- PLI Scheme) योजना:
 - इलेक्ट्रिक वाहनों सहित वाहनों के घरेलू वनिरिमाण को समर्थन देने के लिये 25,938 करोड़ रुपए का बजटीय परवियय।
- उन्नत रसायन वजिज्ञान सेल (Advanced Chemistry Cell- ACC) के लिये PLI योजना:

- देश में प्रतस्पर्द्धी ACC बैटरी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप स्थापति करने के लिये 18,100 करोड़ रुपए का बजटीय परवियय ।
- GST और छूट में कमी:
 - इलेक्ट्रिक वाहनों पर GST 12 परतशित से घटाकर 5 परतशित की गई है ।
 - इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जर/चार्जिंग स्टेशन पर GST 18 परतशित से घटाकर 5 परतशित की गई है ।
- छूट और शुल्क माफ:
 - बैटरी से चलने वाले वाहनों को परमटि आवश्यकताओं में छूट दी जाती है, उन्हें हरे रंग की लाइसेंस प्लेट प्रदान की जाती है ।
 - सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने राज्यों को प्रारंभिक लागत कम करने के लिये इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड शुल्क माफ करने की सलाह दी ।
- ई-गतशीलता को बढ़ावा देने के लिये जागरूकता पहल:
 - भारत के कॉलेजों/वशिवविद्यालयों और संस्थानों में इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु वभिन्न पहलें ।
 - इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित जागरूकता कार्यक्रमों के लिये इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (ICAT) के साथ सहयोग ।

स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/fame-india-phase-ii>

